

## अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की बैठक में गवर्नर डॉ. या. वे. रेड्डी का वक्तव्य\*

बांग्ला देश, भूटान, भारत और श्रीलंका समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए, अध्यक्ष महोदय,

### वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपनी नवीनतम 'वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक' में वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, उससे हम मोटे तौर पर सहमत हैं। आर्थिक प्रगति के वर्तमान परिदृश्य का एक सकारात्मक पहलू यह है कि परिदृश्य दिनोंदिन अधिक विविधतापूर्ण होता जा रहा है। ऐसे सकारात्मक लक्षण के बावजूद अन्तरराष्ट्रीय तेल कीमतों की निरंतर अस्थिरता और निरंतर बढ़ते वैश्विक असंतुलन प्रमुख चुनौती बने हुए हैं। दूसरी चिन्ता यह है कि अनेक देशों में बचत की तुलना में निवेश की मांग कम बनी हुई है। इसके अलावा हमें बर्ड फ्लू महामारी फैलने की संभावना से जुड़े संकट को भी ध्यान में रखना होगा।

2. अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि के बावजूद 2005 में मुद्रास्फीतिकारक दबाव कम था।

2005 के दौरान वैश्विक 'हेडलाइन' मुद्रास्फीति में थोड़ी तेजी आई, जबकि 'कोर' मुद्रास्फीति नियंत्रित रही। हाल के वर्षों में पूरे विश्व में मुद्रास्फीतिगत प्रत्याशा स्थिर रही जो अंशतः इस तथ्य को दर्शाती है कि केन्द्रीय बैंकों की विश्वसनीयता में विश्वव्यापी वृद्धि हुई है। स्थिर मुद्रास्फीतिगत प्रत्याशा आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के पीछे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैश्वीकरण के कारण हाल के वर्षों में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति पर कुछ रोक लगी है तथा अब तक अधिक सुचिंतित मौद्रिक नीतिगत सख्ती का अनुसरण किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

पहला, मुद्रास्फीतिकारक दबाव उतने मुखर नहीं हैं, लेकिन तेल की ऊँची कीमतों के प्रभाव का दूसरा चरण अभी तक नहीं दिख रहा है क्योंकि अनेक देशों में ऊँची तेल कीमतों का पूरा संचरण नहीं हो पाया है। जब तेल की देशी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अधिक अनुरूप होंगी तब कुछ मुद्रास्फीति कारक दबाव उभर सकते हैं। इसके अलावा खुदरा देशी तेल कीमतें अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के पूर्णतया अनुरूप न होने के कारण तेल आयातक देशों की राजकोषीय और बाह्य स्थिति पर महत्वपूर्ण

प्रभाव डाल सकती हैं। वैश्विक तेल बाजारों के विभिन्न घटकों के बीच जटिल सम्बन्ध और फीड बैक को देखते हुए संभावित समायोजन की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन होगा। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति मजदूरी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से मांग द्वारा निर्धारित और प्रत्याशा द्वारा प्रेरित होगी, जबकि विकासशील देशों में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में आपूर्ति संबंधी कठिनाइयाँ प्रमुख घटक होंगी।

दूसरा, एक आसन्न जोखिम यह है कि हाजिर और वायदा बाजारों में तेल की कीमतों में वर्तमान वृद्धि के इस दौर से मुद्रास्फीतिगत प्रत्याशा में अचानक उछाल आ सकता है। इससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे विकसित देशों में अतिमूल्यांकित आस्ति बाजार, खासकर गृहनिर्माण बाजार में प्रत्याशित सुधार से होने वाली क्षति बढ़ सकती है और चालू लेखा में बढ़ते वैश्विक असंतुलन से अपेक्षित समायोजन का कष्ट बढ़ सकता है।

तीसरा, तेल से इतर पण्यों की कीमतें, खासकर धातुओं की कीमतें भी हाल में बढ़ी हैं जो मुद्रास्फीतिकारक दबावों में और वृद्धि कर सकती हैं।

3. अब यह व्यापक रूप से माना जाता है कि सीमित अतिरिक्त क्षमता और निरंतर भौगोलिक राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। आपूर्ति पक्ष में हम निवेश, तेल संरक्षण उपाय, तेल बाजार संबंधी ऑकड़ों के बेहतर प्रसार और पारदर्शिता तथा बाजार संरचना और व्यवहार में सुधार की आवश्यकता पर जोर देना चाहेंगे। मांग पक्ष में, हमारा विचार है कि मौद्रिक नीति निर्माताओं को निकट भविष्य में मुद्रास्फीति में तेजी के किसी भी संकेत के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। आम तौर पर तेल कीमतों में अचानक वृद्धि का प्रतिकूल असर विकासशील और निम्न आय वाले देशों पर अधिक पड़ता है क्योंकि तेल आयात पर उनकी उच्चतर निर्भरता रहती है। अतः विकासशील देशों की आबादी के बड़े वर्ग के कल्याण पर बढ़ती तेल कीमतों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

4. वर्ष 2005 के दौरान वैश्विक वित्तीय स्थिति अनुकूल रही, जो असामान्य रूप से न्यून जोखिम प्रीमियम और न्यून अस्थिरता से स्पष्ट है। ऐसा अंशतः इसलिए है क्योंकि मूलभूत संकेतक सुदृढ़ हैं और प्रतिफल पाने का प्रयास निरंतर बना हुआ है। परन्तु वित्तीय बाजारों में कुछ अतिरेक के प्रमाण मिल रहे हैं, जो उच्चतर इक्विटी मूल्यों और

\* वाशिंगटन डी.सी. में 22 अप्रैल 2006 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख डॉ. या.वे. रेड्डी, गवर्नर का वक्तव्य।

ऋण में तेज वृद्धि से स्पष्ट है। बाजार में अचानक 'करेक्शंस' होने की स्थिति में विकासशील बाजारों की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। इसके अलावा वैश्विक अल्पावधिक ब्याज दरों का बढ़ना जारी है जिससे खासकर विकसित देशों में प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) सपाट हो गया है। जहाँ तक नवीनतम वित्तीय उत्पादों का सम्बन्ध है, क्रेडिट डेरिवेटिव और स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट बाजारों में पिछले कुछ वर्षों में तेज वृद्धि हुई है, जिससे बैंकों के ऋण जोखिम कम हो गए हैं। यद्यपि यह एक स्वागत योग्य विशेषता है, तथापि यह आवश्यक है कि जोखिम के घटकों के आकार और उनकी संरचना, जोखिम अंतरण का आधार और दिशा पता करने की प्रणाली विकसित की जाए तथा अर्थव्यवस्था में जोखिम का वितरण पता चल सके।

5. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी संबंधी गतिविधियों में वित्तीय क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बेहतर फोकस और विश्लेषणात्मक विषयवस्तु का स्वागत करते हैं। यद्यपि वित्तीय बाजार की स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं तथापि उच्चतर ब्याज दरें और ऋण चक्र में परिवर्तन जैसी चक्रीय घटनाएँ वित्तीय बाजारों और संस्थाओं के लिए चुनौती बन सकती हैं। निकट भविष्य में वित्तीय बाजारों की सुदृढ़ता की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि वित्तीय बाजारों की दिन-ब-दिन स्पष्ट होती कमजोरी से मैक्रोइकनामिक आघात लगने की संभावना है।

6. वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में, वैश्विक असंतुलन के बढ़ते स्तर के प्रति अव्यवस्थित समायोजन और राष्ट्रों तथा राष्ट्र समूहों के बीच बदलते असंतुलन का जोखिम बना हुआ है। ऐसा घटित होने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि यूरो क्षेत्र और जापान में मौद्रिक नीति का रुख समायोजनात्मक होने के बजाय अधिक तटस्थ होता जा रहा है। यदि विनिमय दरों और आर्स्ति मूल्यों में गिरावट और तेज उतार-चढ़ाव आया तो निवल तेल आयातक विकासशील देशों पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

7. समग्र रूप से यह एक उत्साहवर्धक तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों से चक्रीय घटक अत्यंत अनुकूल रहे हैं। निम्न ब्याज दरों और चलनिधि की पर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रबल विश्वव्यापी आर्थिक सुधार हुआ है और अधिक प्रतिफल की खोज की प्रक्रिया आरम्भ हुई है। वित्तीय, कापॉरिट और घरेलू क्षेत्रों के तुलन पत्रों में तेज सुधार होने के कारण प्रमुख वित्तीय प्रणालियों में आघात से बचाव के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय साधन निर्मित हुए हैं। नए बाजारों में बैंकिंग क्षेत्र सुधार और बेहतर पर्यवेक्षण के कारण बैंकिंग प्रणाली आम तौर पर मजबूत हुई है। परन्तु यदि वैश्विक असंतुलन के साथ अचानक समायोजन करना पड़ा तो आम तौर पर यह माना जा रहा है कि परिणाम अत्यन्त कठोर हो सकते हैं और अनिश्चित परवर्ती परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कोष के स्तरीय मूल्यांकन का समर्थन करता हूँ, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और प्रकटीकरण बढ़ाया जाए ताकि संक्रमण जोखिम की सम्भावना कम की जा सके।

### अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की मध्यावधिक रणनीति का कार्यान्वयन

8. मैं प्रबंध निदेशक को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोष की मध्यावधिक रणनीति को स्पष्ट किया। मैं समर्थक रिपोर्टों के लिए कार्यकारी दलों के सदस्यों का भी आभारी हूँ। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पिछले डेढ़ दशक में पूरे विश्व में उदारीकरण / वैश्वीकरण की रणनीति अधिकाधिक अपनाए जाने और तेज प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष के कारण वैश्विक आर्थिक / वित्तीय वातावरण में मौलिक परिवर्तन हुआ है। इससे वैश्विक पूंजी बाजार के एकीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित हुई है, जिसके फलस्वरूप निजी पूंजी प्रवाह की मात्रा और प्रकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

9. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थापत्य का आधार एक स्थिर वैश्विक प्रणाली के उदय से जुड़े मुद्दों पर टिका हुआ है। मेरे विचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हो रहे स्वतंत्र परिवर्तनों के प्रति विकास के भिन्न भिन्न चरणों में अवस्थित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जा रहे समायोजन की गति में एकरूपता लाना है। एक स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए जो विश्व समुदाय प्रयास कर रहा है वह तीन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की मान्यता पर आधारित होगा।

पहला, विभिन्न देशों की अलग-अलग वास्तविकताओं और भिन्न भिन्न 'समायोजन गति' को देखते हुए सुधार संबंधी कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता तथा सुधार संबंधी पहल, विषयवस्तु और समय दोनों दृष्टियों से स्वेच्छा पर आधारित होनी चाहिए।

दूसरा, नवोदित बाजार अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय संचालन के स्थापित ढाँचे में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए क्योंकि वैश्विक विकास का स्वरूप बदला है और नवोदित बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस कटु सत्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि वित्तीय स्थापत्य में नई व्यवस्था तब तक सफल रूप से कार्य नहीं कर सकती जब तक कि विकसित और विकासशील देशों या पूंजी अधिशेष और कम पूंजी वाले देशों के बीच बराबर की सहभागिता न हो।

तीसरा, वैश्विक नीति के क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया में समन्वय करने के लिए क्षेत्रीय निकायों और समूहों के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में अनेक ऐसे तत्वों की भूमिका बढ़ेगी जो किसी एक राष्ट्र की सीमा से परे होंगे।

### निगरानी

10. पिछले कुछ वर्षों में निगरानी में, विषय और साधन दोनों दृष्टि से मौलिक परिवर्तन आया है। परन्तु जहाँ तक निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रश्न है, हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ हमारे पास निगरानी के अनेक साधन हैं परन्तु अनेक कारणों से उनकी प्रभावशीलता के संबंध में अभी भी संदेह है। विवाद के प्रमुख मुद्दे अभी भी 'तटस्थता', 'प्रभावोत्पादकता' में वृद्धि 'हस्तक्षेप' में कमी और कोष की निगरानी की

‘निरोधात्मक’ प्रवृत्ति को मान्यता देने पर केंद्रित हैं। मेरे विचार में मुख्य चुनौती यह है अंतिम उद्देश्यों पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय निगरानी प्रणालियों को प्रभावी रूप से कैसे एकीकृत किया जाए। मैकडोनो रिपोर्ट और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम और बहुपक्षीय निगरानी पर स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है। हाल में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम पर स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऐसे देश, जो प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या जिनकी वित्तीय प्रणाली कमजोर है, उनमें से लगभग 20-25 प्रतिशत देशों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों को वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि करनी चाहिए तथा साथ ही इस कार्यक्रम के स्वैच्छिक स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए।

11. हमारा दृष्टिकोण है कि तेजी से एकीकृत होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निगरानी के मुद्दों के बीच वस्तुतः परस्पर पोषण का संबंध रहता है। बहुपक्षीय निगरानी की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों, खासकर औद्योगिक देशों द्वारा अनुसरण की गई नीति के संभावित परिणामों को किस हद तक शामिल किया गया है, क्योंकि वैश्विक वित्तीय प्रवाह का महत्वपूर्ण अंश इन देशों से संबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं दो मुद्दों पर जोर देना चाहूंगा।

पहला, यद्यपि विनिमय दर निगरानी बढ़ाने का हम समर्थन करते हैं, तथापि हम यह मानते हैं कि पूंजी गतिशीलता के साथ विनिमय दर निर्धारण के क्षेत्र में और तकनीकी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि विनिमय दर मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान बढ़े और इन पर आम सहमति विकसित हो। नवोदित बाजारों की विनिमय दर संबंधी संवेदनशीलता को देखते हुए कोष को इन मुद्दों पर विश्वस्त सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका को संतुलित करना होगा। अतः, वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक में विनिमय दर मूल्यांकन को प्रकाशित करने पर विचार करना अत्यन्त असामयिक होगा।

दूसरा, मैक्रोइकनामिक और वित्तीय बाजार विश्लेषण को समन्वित करने के मुद्दे पर हमारा यह विचार है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के साथ-साथ ‘वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक’ बहुपक्षीय निगरानी के लिए कोष का प्रमुख प्रकाशन बना रहे।

12. जहाँ तक द्विपक्षीय निगरानी का संबंध है हम कोष के इस निर्देश से मोटे तौर पर सहमत हैं कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए तथा बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाए जाएँ। परन्तु कोष के पारंपरिक समष्टि आर्थिक अभिमुख निगरानी प्रणाली में किंचित परिवर्तन करते हुए कोष की राष्ट्र निगरानी प्रणाली में वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को केन्द्र में रखने के सुझाव पर सही दृष्टिकोण से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कोष के सदस्यों के वित्तीय क्षेत्र के विकास के भिन्न-भिन्न स्तर हैं और इसलिए एक ही दृष्टिकोण को सभी पर लागू करना

अनुचित होगा। अतः वित्तीय क्षेत्र विश्लेषण के विषय और उन पर दिया जाने वाला बल अलग-अलग राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों के लिए अलग-अलग होगा। यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वित्तीय क्षेत्र पर अतिरिक्त बल देते समय अनुच्छेद IV परामर्श के अंतर्गत मैक्रोइकनामिक विश्लेषण के पारंपरिक परिशुद्धतावादी रुख में नरमी न लाई जाए क्योंकि यह क्षेत्र कोष की मुख्य क्षमता का क्षेत्र है।

### उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कोष की भूमिका

13. जैसा कि पहले संकेत किया गया है, हमारा विचार है कि सहकारी संस्था के रूप में कोष का महत्व इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि वह तेज वृद्धि करने वाली नवोदित बाजार अर्थव्यवस्थाओं की बदलती आकांक्षाओं को अपने कार्य और संचालन की संरचना में कितनी कुशलता के साथ आत्मसात् करता है। हाइ एक्सेस कंटिजेंट फाइनेंसिंग के ढाँचे में संशोधन का प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन काफी कुछ इस लिखत के डिजाइन पर निर्भर करेगा।

### कोष का शासन

14. हमने यह बात बार-बार कही है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शासन संबंधी संरचना की वैधता स्थापित करने के लिए आवाज और प्रतिनिधित्व का मुद्दा महत्वपूर्ण है। यह खेद की बात है कि यद्यपि गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के सापेक्षिक महत्व और वजन में भारी बदलाव आया है, तथापि अंतरराष्ट्रीय समुदाय 1998 के बाद से कोटे में संशोधन नहीं कर पाया है। वस्तुतः 1998 का संशोधन भी अस्थायी स्वरूप का था। कोटे की समग्र समीक्षा और उनके पुनः आबंटन की आवश्यकता के सम्मुख अस्थायी वृद्धि वाली द्विस्तरीय प्रक्रिया संगत नहीं है। वैधता को संपुष्ट करने के लिए कोटे का समग्र वितरण किसी अल्पकालिक और अस्थायी दृष्टिकोण से नहीं प्राप्त किया जा सकता।

15. अध्यक्ष महोदय, हाल के वर्षों में वैश्विक वृद्धि और स्थिरता में भारत के योगदान की सराहना अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने की है। इस संदर्भ में वर्तमान प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के कोटे में भारत के अंश में गिरावट को संगत ठहराना कठिन होगा। इसके अलावा, यदि बहुप्रशांसित ‘ब्रिक्वट’ (ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन) देशों में से 4 में से 3 के कोटे घटा दिए जाते हैं, भले ही ऐसा अल्प अवधि के लिए ही हो, तो मैं नहीं सोचता इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैधता में वृद्धि होगी। जहाँ तक द्विचरणी प्रक्रिया का संबंध है कतिपय क्षेत्रों से यह सुझाव दिया जा रहा है। पहले चरण के संबंध में आम सहमति के लिए आवश्यक है कि दूसरे चरण के ढाँचे पर भी सहमति हो। परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि दूसरे चरण के मूल ढाँचे के संबंध में अभी ही सहमति सम्भव हो पाती तो द्विचरणी प्रक्रिया का औचित्य ही समाप्त हो जाता। 24 देशों के समूह (जी-24) ने अपनी नवीनतम विज्ञप्ति में एक समग्र पैकेज का जोरदार समर्थन किया है जिसमें एक निश्चित समय के भीतर सभी प्रमुख मुद्दों पर एक साथ कार्रवाई

की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी कार्य आरंभ करने के पहले एक सुदृढ़ राजनीतिक आम सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

### निम्न आय वाले देश : बहुपक्षीय ऋण कटौती पहल (एमडीआरआइ)

16. एम डी आर आइ ऋण राहत पहल के कार्यान्वयन में जो प्रगति हुई है, उसे हमने नोट किया है। भविष्य में निम्न आय वाले देशों में कोष को सभी शेष चुनौतियों का सामना करना चाहिए तथा ऋण निर्वहनीयता सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र द्वारा प्रेरित आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने तथा गरीबी में कमी लाने वाली नीतियों और संस्थाओं को समर्थन देना चाहिए। एमडीआरआइ ऋण राहत के साथ-साथ एक प्रभावी निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिए जो कोष द्वारा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग पर नजर रख सके। हमारा विचार है कि इस संबंध में देश-आधारित दृष्टिकोण अपनाया महत्वपूर्ण होगा।

### क्षेत्र के देशों में विकास

17. मैं अब अपने क्षेत्र के विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलु की चर्चा करना चाहूंगा। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्याशा से अधिक 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक तेल अनिश्चितताओं के कठोर प्रभाव के बावजूद मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के सही संयोग से मुद्रास्फीति प्रत्याशा को स्थिर रखने में सहायता मिली है और मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत पर नियंत्रित रही है। अर्थव्यवस्था में निवेश मांग में वृद्धि के अनुरूप चालू लेखा घाटे में वृद्धि हुई, जिसका आसानी से वित्तपोषण हुआ क्योंकि पूंजी प्रवाह में तेजी बनी रही। वित्तीय बाजार आम तौर पर स्थिर रहे। वैश्विक मुद्रा बाजार की घटनाओं की प्रतिक्रिया में भारतीय रुपया पर्याप्त लचीलापन दर्शाता रहा है। सामाजिक क्षेत्र को विशाल आबंटन किए जाने के बावजूद राजकोषीय स्थिति प्रत्याशा से बेहतर रही। वर्ष 2006-07 के संबंध में संभावना सकारात्मक है और नीतिगत प्रयास यह है कि मूल्य स्थिरता के साथ संगति रखते हुए विकास गति बनाई रखी जाए और साथ ही परिस्थिति

के अनुसार तुरंत कदम उठाने के लिए तैयार रह जाय। हम वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम द्वारा निर्धारित बेहतर राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण के प्रति वचनबद्ध हैं, जो मैक्रोइकनामिक स्थिरता के लिए शुभ संकेत है।

18. बांग्ला देश में 2005 के दौरान 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर बनी रही। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि और तेज आयात वृद्धि के बावजूद भुगतान संतुलन के चालू खाते में सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत का सामान्य घाटा हुआ। विशेष रूप से यह बात आश्चर्य करती है कि 2005 के दौरान रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2006 के दौरान आर्थिक सम्भावना सकारात्मक बनी हुई है। गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक कार्यक्रमों और व्यापक आधार वाले माइक्रो-क्रेडिट कार्यक्रमों की सहायता से प्रति व्यक्ति वृद्धि-दर सकारात्मक रही, जिससे निर्धनता के स्तर में काफी कमी आई है। संरचनात्मक सुधार के शेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्राधिकारी ध्यान दे रहे हैं।

19. सुनामी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अच्छी प्रगति हो रही है। वर्ष 2005 के दौरान सकल देशी उत्पाद में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च 2006 तक मुद्रास्फीति घटकर एक अंकीय रह गई है। भुगतान संतुलन अधिशेष में है तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। नवम्बर 2005 में निर्वाचित नए राष्ट्रपति द्वारा घोषित सरकार की आर्थिक दृष्टि यह है कि एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित की जाए जिसमें बाजार को प्रोत्साहन देने वाले वातावरण में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का परस्पर पूरक रूप में सह-अस्तित्व हो। सभी क्षेत्रों के तेज और समान विकास के लिए तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

20. भूटान ने अपने देश में निर्मित विकास रणनीति का अनुसरण किया है जिसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति 5 -5.5 प्रतिशत की निम्न दर पर बनी रही। 18 प्रतिशत की प्रत्याशित वृद्धि दर के साथ 2006-07 और संभावनापूर्ण हो गया है। राजकोषीय स्थिति में थोड़ा अधिशेष हो सकता है तथा विद्युत निर्यात में वृद्धि के कारण चालू लेखा घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे रहने की संभावना है।